CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 27 ▫ अंक- 358 ▫ रायपुर, मंगलवार 21 जनवरी 2025 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

गरियाबंद में मुठभेड़, 20 नक्सली ढेर

गरियाबंद, 21 जनवरी (हाईवे चैनल)। ओडिशा-छत्तीसगढ़ बॉर्डर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों की बीच हुई मुठभेड़ में जवानों को बड़ी सफलता मिली है. मुठभेड़ में 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मारे गये नक्सलियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। वहीं 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिये गये हैं। इनमें दो महिला नक्सली भी शामिल है. वहीं मौके से एके 47, एसएलआर, आईएनएसएएस और अन्य स्वचालित हथियार बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। आईजी रायपुर जोन अमरेश मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है।

मैनपुर थाने क्षेत्र में जवानों ने 60 से अधिक नक्सलियों को चारों तरफ से घेरा

गरियाबंद में सुरक्षाबल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में आधिकारिक तौर पर अब तक 16 नक्सली ढेर हो गए हैं। मुठभेड़ में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता मिली। अभी भी मुठभेड़ जारी है। मारे गए नक्सलियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इससे पूर्व बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 18 नक्सलियों को मार गिराया था। सभी मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। रविवार सुबह से मंगलवार की सुबह तक रुक-रुक कर फायरिंग हो रही है। गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी जंगल में कुल एक हजार से अधिक जवानों ने 60 से अधिक नक्सलियों को चारों तरफ से घेर रखा है। यह मामला मैनपुर थाने इलाके का बताया जा रहा है। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के कोबरा यूनिट का एक जवान भी घायल हुआ है, जिसे एयर लिफ्ट करके रायपुर लाया जा रहा है। इससे पहले रविवार को हुई मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर किए गए थे वहीं एक जवान भी घायल हुआ था।

जवानों को मिली कामयाबी सराहनी : विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना अंतर्गत कुल्हाड़ीघाट क्षेत्र में सुरक्षाबलों की नक्सलियों के साथ रविवार रात से अब तक जारी मुठभेड़ में 20 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मार्च 2026 तक देश-प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षाबल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जवानों को मिली यह कामयाबी सराहनीय है। उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं। हमारी डबल इंजन की सरकार में निश्चित ही हमारा छत्तीसगढ़ मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होकर रहेगा।

कार से एक करोड़ रुपए कैश बरामद

दुर्ग, 21 जनवरी (हाईवे चैनल)। आचार संहिता लागू होने के बाद अंजोरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक कार की डिग्गी से एक करोड़ रुपए कैश मिला है। पुलिस ने कैश को जब्त करते हुए इनकम टैक्स के हवाले कर दिया है।

आचार संहिता लगते ही पहला मामला आया सामने

मिली जानकारी के अनुसार आचार संहिता लगने के बाद अंजोरा चौकी के पास पुलिस ने सोमवार शाम को वाहन चेकिंग कर रही थी। राजनांदगांव से दुर्ग जिले में आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। रात करीब ८ बजे चेकिंग करने वाले पुलिस अधिकारी ने एक कार को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार की डिग्गी से एक करोड़ रुपए कैश मिला। पुलिस ने तत्काल उसे ज4त किया। इसके बाद इनकम टै1स डिपार्टमेंट को सूचना दी गई। बताया जाता है कि जिस व्यक्ति की कार में एक करोड़ रुपए पकड़ाया है उसका नाम चंद्रेश राठौर है और राजनांदगांव जिले का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि स्वराज ट्रै1टर का उसका शोरूम है। वहीं का कैश लेकर वो जा रहा था। १० लाख रुपए से अधिक कैश लेकर चलना गैर कानूनी है। इसलिए पुलिस ने कैश को इनकम टै1स के हवाले किया है।

ब्रेकिंग न्यूज

मोदी ने मणिपुर को अमित शाह को किया आउटसोर्स : कांग्रेस

नई दिल्ली, 21 जनवरी (न्यूज चैनल)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक ताजा हमले में, कांग्रेस ने मंगलवार को दोहराया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर की आउटसोर्सिंग करना प्रधान मंत्री पद की जिम्मेदारी का त्याग है, और पीएम से तुरंत संघर्षग्रस्त राज्य का दौरा करने की मांग की। पार्टी का यह हमला पीएम मोदी द्वारा आज तड़के त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के लोगों को उनके राज्य दिवस पर बधाई देने के बाद आया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि यदि मणिपुर की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री के मन में जरा भी चिंता है तो उन्हें राज्य का दौरा करना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से मणिपुर के लोगों को उनके राज्य दिवस पर शुभकामनाएं भेजी हैं। हालांकि 3 मई, 2023 को मणिपुर की पीड़ा शुरू होने के बाद से उन्होंने, थोड़े समय के लिए भी मणिपुर का दौरा करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि वह पूरी दुनिया में कई जगह गए हैं, लेकिन इंफाल और राज्य के लोगों तक पहुंचने के लिए उन्हें समय नहीं मिला या इसमें उनकी रुचि नहीं है।

शादी के लिए राजी नहीं थे माता-पिता, प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान

नई दिल्ली, 21 जनवरी (न्यूज चैनल)। गाजियाबाद के एक कपल ने सोमवार को ट्रेन के आगे कूदकर कथित तौर पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने शवों को देखा और उन्हें इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डीसीपी ग्रामीण एसएन तिवारी ने बताया कि मृतकों की पहचान सागर (21) और विशाखा (19) के रूप में हुई है। दोनों मोदीनगर थाना क्षेत्र के सिंकरी खुर्द गांव के रहने वाले थे। पुलिस उपायुक्त एसएन तिवारी ने आगे बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह कपल रिलेशनशिप में था और शादी करना चाहता था, लेकिन उनके माता-पिता की इसमें मंजूरी नहीं थी। जिसके चलते इस कपल ने ऐसा कदम उठाया है। उन्होंने कहा, कपल को आखिरी बार रविवार दोपहर करीब 2 बजे एक पार्क में साथ बैठे देखा गया था और सोवमार की सुबह करीब 8 बजे रेलवे ट्रैक के पास उनके शव मिले। कथित तौर पर यह प्रेमी जोड़ा तीन दिन से अपने घर से गायब था।

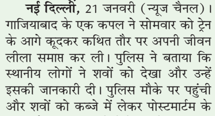

चूहा- सुनती हो, प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है।
चुहिया- हां जी, अब झूठे वादे करने वालों का बाजा भी बजेगा!

पंचायती राज संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती

बिलासपुर, 21 जनवरी (हाईवे चैनल)। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों ने तर्क रखा, अब मामले की सुनवाई 27 जनवरी को होगी। बता दें कि याचिकाकर्ता नरेश रजवाड़े ने अपने अधिवक्ता शक्तिराज सिन्हा द्वारा लगाई अपनी याचिका में कहा कि राज्य सरकार बीते वर्ष 3 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश -2024 ला चुकी है। जिसमें ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129(ड.) की उपधारा (03) को विलोपित कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया कि अध्यादेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के 16 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक के सत्र में इस महत्वपूर्ण अध्यादेश को पारित नहीं कराया गया है, केवल इसे विधानसभा के पटल पर रखा गया है, जिसके कारण यह अध्यादेश वर्तमान में विधि-शून्य और औचित्यहीन हो गया है।

मामले में दोनों पक्षों ने रखा तर्क 27 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

वहीं राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने कहा 3 दिसंबर 2024 को अध्यादेश लाया गया था। वहीं 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 को विधानसभा की बैठक में रखा गया। इस अध्यादेश को पारित होने को लेकर अनुच्छेद 213(2) के तहत राज्यपाल से सहमति है। वहीं संवैधानिक रूप से 6 सप्ताह का समय है। जो 27 जनवरी 2025 को पूरा होगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शक्ति राज सिन्हा ने कैबिनेट की पूर्व बैठक में सार्वजनिक किए एक निर्णय पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इसमें आरक्षण संबंधी संशोधन अध्यादेश को 6 महीने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वहीं नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के नोटिफिकेशन जारी होने के याचिका पर प्रभाव की बात भी कही। जिस पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को गंभीरता से सुना और अपने आदेश में शामिल किया है। वहीं शासन के अधिवक्ता के अध्यादेश को लेकर तर्क को सुनते हुए संवैधानिक रूप से 6 सप्ताह का समय 27 जनवरी को पूरा होने पर उसी दिन सुनवाई तय की गई है।

पिकअप और ट्रक में भिडंत, 2 लोगों की मौत, 15 घायल

दुर्ग, 21 जनवरी (हाईवे चैनल)। दुर्ग जिला अंतर्गत ग्राम दनिया (बोरी) में १७ लोगों से भरी पिकअप ट्रक से जा टकराई। इससे दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं १५ लोग घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला बोरी थाना क्षेत्र का है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार रात ८.४५ बजे पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। पिकअप में सवार सभी लोग कुम्हारी के वार्ड ३ के रहने वाले हैं और सभी लोग पिकअप क्रमांक सीजी ०४ पीसी ४०३७ में सवार होकर एक साथ कुम्हारी से लिटिया में जोगी गुफा के महंत के दर्शन के लिए गए थे। वहां से वो लोग वापस कुम्हारी लौट रहे थे। जैसे ही पिकअप लिटिया गांव से दो किमी दूर ग्राम दनिया के पास पहुंची रात में ड्राइवर देख नहीं पाया। सामने अचानक धान से भरा ट्रक देखकर पिकअप अनियंत्रित हो गया और तेज रफ्तार में ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप के सामने का पूरा हिस्सा चिपट गया और पिकअप वहीं पलट गई। इससे उसमें सवार लोग उसके नीचे दब गए। गाड़ी के नीचे दबने से मणिकांत पटेल की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद एक अन्य ने रास्ते में दम तोड़ दिया।

राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप के ताबड़तोड़ फैसले कई कार्यकारी आदेशों पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली, 21 जनवरी (न्यूज चैनल)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पदभार संभालने के पहले ही दिन कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इसमें पेरिस जलवायु समझौता और विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को बाहर लाना, प्रतिबंध से बचने के लिए टिकटॉक को 75 दिन का समय देने और क्षमादान शक्तियों का उपयोग समेत कई फैसले शामिल हैं। इससे पहले ट्रंप ने सोमवार रात (भारतीय समयानुसार) अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की।

इसके लिए आयोजित समारोह में दुनिया की बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भी मौजूद थे। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चैन, अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस और उनकी मंगेतर लॉरैन सांचेज, साथ ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक एलन मस्क भी समारोह में मौजूद थे। एपल के सीईओ टिम कुक और टिकटॉक के सीईओ शोउ ज़ी च्यू भी समारोह में मौजूद थे।

आरजी कर मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंची ममता सरकार

संजय रॉय के लिए मांगी मौत की सजा

नई दिल्ली, 21 जनवरी (न्यूज चैनल)। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले में संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के सियालदह कोर्ट के फैसले के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है। महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक की खंडपीठ में याचिका दायर की है। मामले को दायर करने की अनुमति दे दी गई है।

इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को सियालदह कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दे दी, जिसमें आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने मामले में एकमात्र दोषी रॉय को मृत्युदंड देने की मांग करने के लिए न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में अपील दायर करने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने सियालदह में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास के आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट से अपील दायर करने की अनुमति मांगी थी।आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की मौत मामले में आरोपी संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी असंतोष जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि यह दुर्लभतम अपराध था, इसमें दोषी को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए थी। उन्होंने सोमवार को कहा था कि संजय राय की फांसी की मांग को लेकर बंगाल सरकार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इससे पहले आरजी कर मामले में सोमवार को सजा का एलान कर दिया गया था। कोर्ट ने दोपहर 2.45 बजे अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सियालदह अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। सियालदह कोर्ट के जज अनिरबन दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है। पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा और 7 लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाना चाहिए।

केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए बनेगा बोर्ड

भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र

नई दिल्ली, 21 जनवरी (न्यूज चैनल)। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 'संकल्प पत्र' को जारी किया। भाजपा तीन चरणों में संकल्प पत्र जारी कर रही है। जिसमें से आज दूसरा भाग जारी किया गया है। जिसमें दिल्ली की जनता से कई वादे किए गए हैं। संकल्प पत्र के दूसरे भाग को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जारी किया है।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। दो बार की यात्रा और आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति भी होगी। यह मोदी की गारंटी है। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, तो विकसित दिल्ली की एक अहम भूमिका है। विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 के संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आपके सामने पहले अपनी बात रखी थी, आज उसके दूसरे भाग को लेकर मैं आप सबके सामने आया हूं। आगे कहा कि हमारी सरकार बनने पर हम स्वास्थ्य, यातायात, बिजली, पानी और परिवहन आदि से जुड़ी समस्याओं का हल करेंगे। दिल्ली वालों को बेहतर आज और बेहतर कल देने का प्रयास करेंगे। भाजपा की जहां भी सरकारें रही, जन-कल्याण उनकी प्राथमिकता और केंद्र बिंदु रहा। केंद्र सरकार में भी हमने राज्यों के सहयोग से नागरिकों की समस्याओं का जहां समाधान किया, वहीं पर उनको सुविधाएं भी दी। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने दलालों को खत्म कर दिया है। डीबीटी के माध्यम से जन-कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। भ्रष्टाचार के प्रति मोदी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। दिल्ली के सरकारी शिक्षण संस्थानों में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

CMYK